UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

JULY, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 310

NEWSMAKERS

गन्ने की खेती में हो रहा है ड्रोन का इस्तेमाल, किसानों के पैसा और समय की हो रही बचत

पीलीभीत : गन्ना किसानों के सामने वर्तमान में श्रमिकों की कमी एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन अब गन्ने की खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल से इस समस्या से किसानों को कुछ हदतक राहत मिली है। किसानों के अनुसार, पैसा और समय दोनों की बचत हो रही है। इतनाही नही किसान अब ट्रेंच विधि के साथ गन्ने के साथ सह फसली लेकर अपनी आय बढ़ा रहा है। गन्ना खेती में नई तकनीक के रूप में दवाओं के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। एक ड्रोन से पूरे खेत में आसानी से दवाओं का स्प्रे किया जा रहा है। जनपद भर में एलएच चीनी मिल पीलीभीत, दि किसान सहकारी चीनी मिल पूरनपुर, दि किसान सहकारी चीनी मिल बीसलपुर, बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल बरखेड़ा संचालित हो रही है, जहां पर लाखों किसान संबद्ध है।

हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार, गन्ने की खेती को फायदे की दिशा में मोड़ा जा रहा है। इसके लिए किसानों को नई सुविधाएं दी जा रही है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से गन्ना खेती में क्रांति दिख रही है। कम समय में किसान अपने खेतों में कीट नियंत्रण, खाद का छिड़काव कर पा रहे हैं, जिसके लिए ज्यादा श्रमिकों की भी आवश्यकता नहीं होती है। आधुनिक तकनीक से गन्ना खेती आसान और लाभकारी बनी है। किसानों को ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव प्रदीप अग्निहोत्री ने बताया कि जनपद में इफको के पास तीन ड्रोन हैं, जो किसानों को किराए पर आसानी से उपलब्ध हैं। डीसीओ खुशीराम ने कहा कि, किसान गन्ने की खेती में ड्रोन का प्रयोग कर रहा है। हर काम सटीक और समयबद्ध ढंग से हो रहा है।

Source: Chinimandi, 23rd June, 2025

उत्तर प्रदेश में 243 किस्मों के साथ गन्ना खेती को बढ़ावा देने का प्रयास

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को सशक्त बनाने के लिए 243 बेहतर किस्म के गन्ने का विकास कर रही है, जिससे उन्हें अधिक आय और समृद्धि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह पहल राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सभी हितधारकों के लिए गन्ना खेती को अधिक लाभदायक बनाने के सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

अधिक उत्पादक और लाभदायक गन्ने की किस्मों को पेश करके, राज्य खेती को एक फायदेमंद उद्यम में बदल रहा है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद ने जलवायु-लचीली और रोग-प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री योगी की देखरेख में, किसानों को समय पर तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य भर में गन्ना समितियों को भी मजबूत किया जा रहा है। पिछले दस वर्षों में, राज्य ने विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल गन्ने की कई किस्में विकसित की हैं। वर्तमान में, 59 प्रमुख किस्मों की सफलतापूर्वक खेती की जा रही है, जिनमें 28 जल्दी पकने वाली और 31 मध्यम से देर से पकने वाली किस्में शामिल हैं। इन किस्मों ने किसानों को अधिक उपज और बेहतर लाभ दिलाने में योगदान दिया है। अब तक कुल 243 उच्च प्रदर्शन वाली गन्ना किस्में विकसित की जा चुकी हैं। इसी तरह 267 हेक्टेयर में विकसित प्रजनक बीज नर्सरी गन्ना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।

इस नर्सरी के माध्यम से किसानों को प्रमाणित, रोग मुक्त बीज मिल रहे हैं, जिससे उनकी फसलों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। नवाचार के माध्यम से विकसित की गई नई किस्में कीटों और बीमारियों के प्रति मजबूत प्रतिरोध प्रदर्शित करती हैं। हाल ही में की गई इन पहलों से फसल की क्षति कम हुई है, उत्पादन लागत कम हुई है और किसानों का मुनाफा बढ़ा है। नतीजतन, पूरे राज्य में लाखों गन्ना किसान सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इस बीच, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और किसानों को बीज, उर्वरक, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करने में गन्ना समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है।

Source: Sugar times, 23rd June, 2025

उत्तर प्रदेश ने गन्ना किसानों के लिए पायलट माइक्रो-सिंचाई योजना शुरू की, इस पहल से 25,000 हेक्टेयर होगा कवर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग ने ड्रिप सिंचाई पर एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी 45 गन्ना उत्पादक जिलों में उप-भूमि जल का संरक्षण करना और क्षारीय और असमान क्षेत्रों में गन्ने की खेती को सक्षम बनाना है। अधिकारियों ने कहा कि, यह पहल 25,000 हेक्टेयर को कवर करती है और इससे 20,000 से 25,000 गन्ना किसानों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

पायलट परियोजना के परिणामों के आधार पर, माइक्रो-सिंचाई योजना को राज्य के लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर के पूरे गन्ना उत्पादक क्षेत्र में विस्तारित किया जाएगा, जिसमें लगभग 5 मिलियन किसान शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि ड्रिप सिंचाई, जो सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती है, पारंपरिक तरीकों की तुलना में अपवाह और वाष्पीकरण से होने वाले पानी के नुकसान को काफी कम करेगी। उपाध्याय ने कहा, "यह उन्नत प्रणाली पूरे खेत को नमी से बचाएगी और खरपतवार की वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित

Continued on the next page ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

JULY, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 310

करेगी। गन्ने की खेती की लागत में काफी कमी आएगी, जबकि उत्पादकता 20-25% बढ़ सकती है।

उन्होंने कहा, सूक्ष्म सिंचाई से असमान और क्षारीय कृषि क्षेत्रों में भी गन्ने की फसल उगाना संभव हो जाएगा, क्योंकि पानी की बूंदों की निरंतर श्रृंखला फसल की जड़ों में उचित रूप से सिंचाई करेगी।" योजना की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सीमांत किसानों को ड्रिप सिंचाई मशीनों और उपकरणों की खरीद पर 90% सब्सिडी प्रदान करेगी, जबकि अन्य सभी श्रेणियों के उत्पादकों को 80% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सभी गन्ना उत्पादक जिलों को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, और परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

Source: Sugar times, 1st July, 2025

एथेनॉल आपूर्ति के लिए अनाज के तरफ ज्यादा आवंटन से चीनी उद्योग चिंतित

नई दिल्ली: चीनी उद्योग की एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने किस्मत बदलने का काम किया है। लेकिन अब उद्योग एथेनॉल के संबंध में चिंतित नजर आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, एथेनॉल की बढ़ती माँग को देखते हुए उद्योग ने नई एथेनॉल उत्पादन क्षमताएँ स्थापित करने और आपूर्ति बढ़ाने में भारी निवेश किया है, लेकिन अब उद्योग एथेनॉल आपूर्ति को लेकर चिंतित है, क्यूंकि उनका मानना है की अब ग्रेन के तरफ ज्यादा झुकाव हो चूका है।

चीनी उद्योग के अनुसार, मोलासेस और अनाज के बीच आवंटन का अंतर बहुत बढ़ गया। एक समय चीनी उद्योग लगभग 70% एथेनॉल की आपूर्ति करता था, जो अब घटकर लगभग 30% रह गया है, और यह कमी अनाज आधारित डिस्टलरीयों द्वारा पूरी की जा रही है। इस प्रतिकूल घटनाक्रम का एथेनॉल से राजस्व सृजन, किसानों को समय पर भुगतान और इष्टतम क्षमता उपयोग के संदर्भ में चीनी उद्योग पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं।

श्री रेणुका शुगर्स के कार्यकारी अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि, नीति आयोग ने चीनी क्षेत्र से 55% और अनाज से 45% एथेनॉल उत्पादन की परिकल्पना की थी। इस समझ के आधार पर, चीनी क्षेत्र ने पूरी तरह से सरकार के वादे पर एथेनॉल के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया। चतुर्वेदी को डर है कि, इस क्षेत्र को सीमित एथेनॉल आवंटन के साथ, ऋण पर ब्याज चुकाना मुश्किल होगा और यह फिर से रुग्णता की ओर बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि सरकार भविष्य की संभावनाओं को समझेगी और मूल शेष राशि को वापस लाएगी। इस साल गन्ने की अच्छी फसल की उम्मीद के साथ, इससे सरकार को चीनी क्षेत्र के लिए आवंटन को आवश्यकता के 55% तक बढ़ाने का आवश्यक विश्वास मिलेगा।"

इंद्रेश्वर शुगर मिल्स लिमिटेड की पूर्णकालिक निदेशक अंकिता पाटिल ने कहा कि, एथेनॉल चीनी मिलों के लिए मार्जिन स्थिरीकरण का एक प्रमुख कारक रहा है। उन्होंने कहा कि, अगर यह प्रवृत्ति जारी रही, तो चीनी उद्योग केवल चीनी पर अत्यधिक निर्भर हो जाएगा, जिससे एथेनॉल द्वारा प्रदान किया जाने वाला विविधीकरण और आर्थिक लाभ समाप्त हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि, इससे उद्योग और भी असुरक्षित हो जाएगा, मोलासेस की कीमतों में गिरावट आएगी और एथेनॉल से होने वाले राजस्व में भारी कमी आएगी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला की, वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव होगा और बुनियादी ढाँचे का कम उपयोग होगा। चीनी उद्योग की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए रणनीतिक योजना और नीतिगत संरेखण आवश्यक होगा।

Source: Chinimandi, 9th July, 2025

बड़ी सफलता: आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने गन्ने की खोई से तैयार किया हाइड्रोजन गैस

वाराणसी : आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने गन्ने की खोई और नाले के बैक्टीरिया से हाइड्रोजन तैयार करने में सफलता पाई है। अमर उजाला में प्रकाशित खबर के अनुसार, ये काम ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रक्रिया के तहत संस्थान के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बायो मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग प्रयोगशाला में हुआ है। इस अध्ययन में एक बैक्टीरिया बायोपॉलिमर को भी मिलाया गया है। इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये गन्ने की खोई (बैगास) को प्रभावी रूप से हाइड्रोजन गैस में बदल देता है।

इसकी ये कार्यक्षमता इसे बायोमास वेस्ट से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए एक जैव प्रेरक बनाती है। यह अध्ययन प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी एंड फ्यूल में प्रकाशित किया गया है। इसके बाद अब इस रिसर्च के लिए एक पेटेंट आवेदन भी दायर कर दिया गया है। इस बैक्टीरिया को एल्केलिजींस अमोनियॉक्सीडेंस सीरम के रूप में एनसीबीआई जीन बैंक में रजिस्टर्ड कर दिया गया है। हाइड्रोजन बनाने के लिए डार्क फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह एक कम ऊर्जा वाली, एनारोबिक (अवायवीय) प्रक्रिया है, जो पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद है।

आईआईटी बीएचयू की वैज्ञानिक प्रो. आभा मिश्रा ने कहा कि, शुरुआती अध्ययन में पाया गया है कि यह प्रजाति पर्यावरण के अनुकूल बायोपॉलिमर बनाने में भी सक्षम है। वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हर साल यहां पर बड़ी मात्रा में खोई निकलती है और खेतों या नालों में फेंक दी जाती है। इससे पर्यावरण प्रबंधन में काफी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इससे कृषि अपशिष्ट उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण की दो महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान भी मिलेगा। प्रो. मिश्रा संस्थान में बायो मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग प्रयोगशाला की प्रभारी और तथा आईआईटी बीएचयू की अनुसंधान एवं विकास की एसोसिएट डीन भी हैं।

Source: Chinimandi, 3rd July, 2025

P.T.O ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

JULY, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 310

Sugarcane insects: गन्ने के 3 बड़े दुश्मन 100 रुपये में होंगे खत्म, केमिकल से मिलेगी छुट्टी, फसल होगी शानदार

मॉनसून में गन्ने को 3 बेधक कीट भारी नुकसान पहुंचाते हैं। रासायनिक दवाओं का छिड़काव मुश्किल और कम प्रभावी होता है। इसका सस्ता और असरदार समाधान है ट्राइकोकार्ड मात्र 100 रुपये में दो कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परजीवी कीट दुश्मनों के अंडे खाकर उन्हें खत्म कर देते हैं। इससे फसल की लागत घटती है और उपज बढ़ती है जिसके बारे में एक्सपर्ट ने खास जानकारी दी है। मॉनसून का मौसम आते ही गन्ने की फसल तेजी से बढ़ने लगती है, और इसी समय गन्ने को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव इस समय मुश्किल हो जाता है, और बारिश के कारण उनका असर भी कम हो जाता है, जिससे किसानों की लागत बढ़ जाती है। हाल के वर्षों में बोरर कीटों से गन्ने की फसल का काफी नुकसान देखा जा रहा है, जिसमें चोटी बेधक कीट (टॉप शूट बोरर) सबसे अधिक हानिकारक है, जो मार्च से लेकर फसल की कटाई तक नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा, जड़ बेधक (रूट बोरर) और तना बेधक (स्टेम बोरर) भी गन्ने को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं।

गन्ने के सबसे बड़े दुश्मन कीट

गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य तीन कीट इस प्रकार हैं-

चोटी बेधक या टॉप शूट बोरर- यह कीट गन्ने की फसल में मार्च से सितंबर तक सभी अवस्थाओं में हमला करता है। इसके प्रकोप से गन्ने की पत्तियां सूखने लगती हैं और पौधे मुरझा जाते हैं, जिसे डेड हार्ट कहते हैं। गन्ने की मध्य शिरा में एक लाल धारी पड़ जाती है और विकसित गन्ने में झाड़ीनुमा सिरा बन जाते हैं, जिससे फसल की वृद्धि रुक जाती है

जड़ बेधक या रूट बोरर- इस कीट की सूंडी (लार्वा) छोटे और बड़े, दोनों ही पौधों पर पाई जाती है। सूंडी जमीन से लगे गन्ने के निचले हिस्से में सुराख बनाकर अंदर घुस जाती है और पौधे को नुकसान पहुंचाती है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। सूखे हुए पौधों से कोई दुर्गंध नहीं आती, जिससे इसका पता लगाना और नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है

तना बेधक या स्टेम बोरर- तना बेधक कीट का प्रकोप विशेष रूप से वर्षा काल के बाद जल भराव की स्थिति में अधिक होता है। यह कीट तनों में छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है और पोरियों के अंदर का गूदा खा जाता है, जिससे उपज में भारी कमी आती है।

100 रुपये में तीनों कीटों से पाएं छुटकारा

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर की कीट वैज्ञानिक डॉ नीलम कुरील ने बताया कि महंगे रासायनिक कीटनाशकों के बजाय, किसान अब ट्राइकोकार्ड का उपयोग करके इन कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक ट्राइकोकार्ड की कीमत बाजार में लगभग 50 रुपये होती है, और गन्ने के एक खेत के लिए आमतौर पर दो कार्ड की जरूरत होती है. यानी कुल 100 रुपये का खर्च, एक ट्राइकोकार्ड में परजीवी कीट ट्राइकोग्रामा (Trichogramma) के लगभग 10,000 अंडे होते हैं।

इन कार्डों को चार-चार टुकड़ों में काटकर खेत में गन्ने की निचली पत्तियों पर रस्सी या स्टेपलर से बांध दिया जाता है। कार्ड में मौजूद परजीवी कीट तितली बनकर निकलते हैं और गन्ने के दुश्मन कीटों जैसे चोटी बेधक, जड़ बेधक और तना बेधक के अंडों को खा जाते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती ही नहीं इस तरह, बेहद कम लागत और आसानी से ये तीनों प्रमुख कीट गन्ने के खेत से खत्म हो जाते है। अगर कीटों का प्रकोप ज्यादा हो, तो हर 15 दिन के अंतराल पर ट्राइकोकार्ड का उपयोग करना चाहिए।

ट्राइकोकार्ड प्रयोग के समय रखें खास ख्याल

जब आप ट्राइकोकार्ड का उपयोग कर रहे हों, तो किसी भी रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे ट्राइकोग्रामा के अंडे या परजीवी मर सकते हैं। बहुत अधिक बारिश के समय ट्राइकोकार्ड का उपयोग करने से बचें, क्योंकि इससे कार्ड पर मौजूद अंडे धुल सकते हैं। यह जैविक तरीका किसानों को हजारों रुपये की रासायनिक दवाओं के खर्च से बचाता है और गन्ने की फसल को तीन सबसे बड़े दुश्मनों से सुरक्षित रखता है। ट्राइकोकार्ड गन्ना शोध संस्थान, चीनी मिलों, कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि से संबंधित दुकानों पर आसानी से मिल जाती है।

Source: Kisan Tak, 3rd July, 2025

ETHANOL BLENDING SAVES 1.3 LAC CR. IN FOREX SAYS-HARDEEP SINGH PURI UNION MINISTER PETROLEUM

New Delhi: India's ethanol blending programme has not only reduced the country's dependence on crude oil imports but also significantly boosted farmers' income, Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, said on Sun day. The Union minister said that over the past 11 years, the government has paid more than Rs 1.18 lakh crore to farmers under the ethanol blending programme.

He added that the initiative has helped India save foreign exchange worth Rs 1.36 lakh crore by cutting down on crude oil imports. "During this period, ethanol has replaced around 232 lakh metric tonnes of crude oil, resulting in a reduction of approximately 698 lakh metric tonnes in carbon emissions," the minister said in a post on social media platform X. "Under the guidance of Prime Mini ster Narendra Modi, ethanol is emerging as a key driver of New India's growth," he added. "Every drop of ethanol carries the pride and prosperity of our farmers. We have already achieved the target of 20 percent ethanol blending ahead of schedule," the Union Minister stated.

Source: Sugar Times, 30th June, 2025

P.T.O ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

JULY, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 310

FAVORABLE MONSOON TO BOOST INDIA'S SUGAR OUTPUT, PRICES WILL REMAIN RANGE-BOUND: CRISIL

New Delhi: India's gross sugar production is expected to rise in the sugar season (SS) 2026, helped by above-average monsoon, boosting cane acreage and yields in key sugar-producing states such as Maharashtra and Karnataka, according to a report by Crisil.

The Crisil report estimates that sugar production is expected to rise by about 15 -35 per cent to 35 million tonnes.

This surge is expected to boost sugar mills and give some relief from the trifecta of challenges, such as high cane costs, subdued ethanol prices and muted exports that compressed their operating profitability by about 200 basis points (bps) to 8.7-9 per cent in FY2025.

With improved supplies and potentially higher diversion of sugar for ethanol blending with petrol, the operating margin of sugar mills is likely to recover to about 9-9.5 per cent in FY 2026. This is likely to support the credit profiles of sugar players, which saw some pressure last fiscal.

Additionally, diversion for ethanol is expected to rise to nearly 4 million tonnes, supported by high sugar output and the government's 20 per cent blending target, as it offers faster cash-flow churn.

"The strategic diversification to ethanol was intended to de-risk the earnings and cash flow of sugar mills. But rising cane costs (cane FRP has been hiked by 4.5 per cent to Rs 355 per quintal for SS 2026) and stagnant ethanol procurement prices have limited improvement in profitability," said Anuj Sethi, Senior Director, Crisil Ratings.

The report adds that despite this rise in sugar production, margins of integrated millers will improve only marginally

"As a result, the operating margin of integrated millers is likely to improve only marginally by 40-60 bps to 9-9.5 per cent despite a 15 per cent jump in sugar output.

That said, standalone millers, lacking distillery or cogeneration power sales, may continue facing margin pressure," noted the report

On the domestic price side, sugar prices have held steady at Rs 35-38 per kg this season. With output expected to rise, sugar prices are likely to remain range-bound, limiting any significant upside in the profitability of sugar millers.

Source: Chinimandi, 27th June, 2025

Top Sugar Producting Countries

Top Sugar Producers	Total production (metric tons)	Global production share %
1. Brazil	43 million	23%
2. India	35.5 million	19%
3. European Union	15.58 million	8%
4. China	11 million	6%
5. Thailand	10.24 million	5%
6. USA	8.42 million	5%
7. Pakistan	6.86 million	4%
8. Russia	6.5 million	3%
9. Mexico	5.4 million	3%
10. Australia	4 million	2%

Knowledge Box

India's first and the world's fifth International Sugarcane Research Center is set to open in the Samastipur district. At present, only four other countries host similar international sugarcane research centres: SASRI in South Africa, the Guangxi Sugar Industry Research Institute in China, the Kibaha Sugar Research Institute in Tanzania, and the Sugarcane Research Institute in Ishurdi, Bangladesh. Once operational, the Pusa-based center in Samastipur will become the fifth such institute globally.

UPSMA Newsletter titled 'Varta' the Dialogue is providing information on sugar, sugar industry and sugar byproducts. We request you to share your thoughts and experience with us through write-ups, success stories, updates, photographs etc. We publish your creative in the next edition of this newsletter. You are requested to send your entries to be published in UPSMA newsletter through mail at upsma@upsma.org. The newsletter will be uploaded on UPSMA website.

अस्वीकरण: यहाँ दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा या अन्य स्रोतों से ली गई है, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है और इस पर इस तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस समाचार में दी गई जानकारी में किसी भी अनजाने त्रुटि से किसी भी व्यक्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए 'वार्ता टीम' किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी। इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी इस समाचार की तारीख तक है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य के परिणाम या घटनाएँ इस जानकारी के अनुरूप होंगी।

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org